

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 22 अगस्त, 2006/31 श्रावण, 1928

# हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

# अधिसूचना

शिमला-171 004, 22 अगस्त, 2006

संख्या वि०स0-विधायन-गवर्न. बिल / 1-40 / 2006.—हिमाचल प्रदेश विधान समा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक

3708

22-8-2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

> जे0 आर0 गाज़टा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान समा।

2006 का विधेयक संख्यांक 15

# हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।
- 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें धारा 2 का इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (6) के संशोधन। पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
- "(6-क). "पशु" से पालतू पशु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंसें, गाएं, बैल, घोड़े, घोड़ियां, खस्सी, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ियां, खच्चरें, गधे, सुअर, मेंढ़े, भेड़ें, मेष, मेमने, बकरियां और बकरियों के बच्चे भी हैं;"।
- 3. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा <sup>धारा</sup> 11-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— अन्तःस्थापन।

"11-क. पशुओं का रिजस्ट्रीकरण और उसके लिए अभिलेख का अनुरक्षरण.—(1) प्रत्येक परिवार का मुखिया, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ से एक मास की अविध के भीतर और तत्पश्चात् समय—समय पर, किसी भी कारण से पशुओं की संख्या में कभी कोई परिर्वतन होता है, उसके परिवार के स्वामित्वाधीन पशु का विवरण या तो मौखिक रूप में या लिखित

रूप में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान या पंचायत सचिव को देने के लिए या दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरों की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायत पशुओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी और उसके अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:

परन्तु ग्राम पंचायत ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगी जैसी ग्राम पंचायत द्वारा नियत की जाए।

- (3) ग्राम पंचायत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा रखे गए कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान के अभिलेख को बनाए रखे।
- (4) प्रत्येक ग्राम पंचायत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसकी अधिकारिता के भीतर भटकते (आवारा) पशुओं की पहचान कराने में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों या प्रतिनिधियों की सहायता करे।
- (5) पहचान चिन्ह वाला कोई पशु यदि भटकता (आवारा) पाया जाता है, तो पशु के स्वामी की पहचान ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा बनाए रखे अभिलेख से करेगी और ऐसा स्वामी प्रथम अपराध के लिए तीन सौ रुपये और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में पांच सौ रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।
- (6) यदि ग्राम पंचायत ऐसे भटकते (आवारा) पशु की पहचान चिन्ह के साथ छेड़छाड़ या उसको विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहती है तो वह ऐसे मामले की रिपोर्ट नजदीकी पशुपालन औषधालय के प्रभारी को करेगी जो भटकते (आवारा) पशु को नजदीकी गौसदन या गौशाला को सौंपेगा।"।

# उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में भटकते (आवारा) पशुओं की समस्या से पार पाने के लिए पशुओं का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य करना और इस कार्य को ग्राम पंचायतों को सौंपना आवश्यक समझा गया है। इसके अतिरिक्त पशुओं के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति भी प्रस्तावित की गई है। इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि इस प्रभाव का उपबन्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में किया जाए। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सत महाजन, प्रभारी मन्त्री।

शिम	ला	******	 
तारी	ख		 

#### (AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT)

Bill No. 15 of 2006

## THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2006

. (As Introduced in the Legislative Assembly)

#### A

#### BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of the India, as follows:—

- Short title.
- 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2006.
- Amendment of section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after clause (6), the following clause shall be added, namely:—
  - "(6-A). "cattle" means domestic animals and includes elephants, camels, buffaloes, cows, oxen, horses, mares, geldings, ponnies, colts, fillies, mules, asses, pigs, rams, ewes, sheep, lambs, goats and kids;".
- Insertion of 3. After section 11 of the principal Act, the following section section 11-shall be inserted, namely:—
  - "11-A. Registration of cattle and maintenance of record therefor.—(1) Head of every family shall be responsible to give or cause to be given, either orally or in writing, the details of cattle owned by his family to the concerned Pradhan or the Panchayat Secretary of the Gram Panchayat, within a period of one month from the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2006, and thereafter every time as and when any change in the number

of cattle takes place by any reasons.

(2) On receipt of the details of cattle under sub-section (1), the Gram Panchayat shall register cattle and shall maintain records thereof in such form as may be notified by the State Government:

Provided that the Gram Panchayat may charge registration fee at such rate as may be fixed by the Gram Panchayat.

- (3) It shall be the duty of the Gram Panchayat to assist the officials or persons engaged by the Animal Husbandry Department for applying appropriate identification mark on each cattle and to maintain the record of identification.
- (4) It shall be the duty of every Gram Panchayat to assist the officials or representatives of the Animal Husbandry Department in identifying the stray cattle within its jurisdiction.
- (5) If any cattle with identification mark is found stray, the owner of the cattle shall be identified by the Gram Panchayat from the record maintained by it and such owner shall be liable to a fine of three hundred rupees for the first offence and five hundred rupees in the event of second or subsequent offence, which shall be imposed by the Gram Panchayat.
- (6) If the Gram Panchayat fails in identifying such stray cattle due to tampering with identification mark or mutilation thereof, it shall report the matter to the In-charge of the nearest Animal Husbandry Dispensary who shall lodge the stray cattle to the nearest Gosadan or Goshala."

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to overcome the problem of stray cattle in the State, it has been considered necessary to make registration of cattle mandatory and to entrust this work to the Gram Panchayats. Further a penalty has also been proposed for contravention of the provisions relating to mandatory registration of cattle. Thus, it has been decided that a provision to this effect be made in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SAT MAHAJAN, Minister-in-charge.

SHIMLA: The , 2006.